International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8
IJSH 2024; 6(1): 04-09
www.sociologyjournal.net
Received: 13-11-2023
Accepted: 15-12-2023

संगीता कुशवाहा
शोधार्थी, शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. किरण सिंह
शोध निर्देशक,
प्राध्यापक / विभागाध्यक्ष,
शा. कन्या. स्नात. महाविद्यालय सतना, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
संगीता कुशवाहा
शोधार्थी, शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

''ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की समकालीन भूमिका व चुनौतियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

संगीता कुशवाहा एवं डॉ. किरण सिंह

सारांश
वर्तमान सामाजिक समता, और न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन का नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है। भारतीय महिलाएँ, और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएँ, घर के अंदर और बाहर भी कई सामाजिक और आर्थिक भूमिकाएँ निभाती हैं, लेकिन समाज में उनके योगदान को उचित मान्यता नहीं मिलती है। उन्हें केवल बाल स्वास्थ्य, पोषण आदि से संबंधित कार्यक्रम में ही सम्मिलित किया जाता हैं। इसका कारण योजनाकारों द्वारा महिलाओं के योगदान और क्षमता को कम माना जाता है। ग्रामीण विकास में महिलाओं की बदलती तस्वीर से परिलक्षित होता है कि महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी में भी वृद्धि हुई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता में भी बढ़ोतरी देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ अब अपने क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं को जानने तथा उनको दूर करने के लिए कार्य भी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा के आयोजन से पहले महिलाओं की एक आमसमा का आयोजन किया जाता है। जिसमें ग्रामीण महिलाएं अपनी समस्याओं को सभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करती है। ग्रामसभा में उन समस्याओं पर विचार–विमर्श करके निवारण किया जाता, इस प्रकार ग्रामीण महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है।

कूटशब्द : परिलक्षित, आमसमा, ग्रामसभा

प्रस्तावना
ग्रामीण विकास में महिलाओं की बदलती तस्वीर से परिलक्षित होता है कि महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी में भी वृद्धि हुई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार के द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु कई योजनाएँ बनाई गई, जिसमें उड़ान योजना, जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना, आदि प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों व महिलाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नेपकीन प्रदान किये जाते हैं। ग्रामीण महिलाएँ छोटे–छोटे लघु उद्योग प्रारम्भ कर रही हैं व कसीदा, सिलाई बुनाई कर स्वंय को आत्मानिर्भर बना रही है। सरकार के द्वारा महिलाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने हेतु लोन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही स्वतत्रंता के पश्चात् भारत में ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं का योगदान निरन्तर बढ़ता ही रहा है। महिलाएँ आत्मनिर्भर बनकर ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर रही है। सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओ के विकास के लिए कई योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकत्तर महिलाएँ कृषि आधारित कार्यों को प्राथमिकता देती थी, लेकिन वर्तमान समय में महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करके गांवों का विकास कर रही है। लेकिन क्या ग्रामीण महिलाएँ सार्थक रूप से ग्रामीण क्षेत्र की ''ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की समकालीन भूमिका व चुनौतियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) में कारगर सहायक हो रही है। इसी सन्दर्भ में यह शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ अब अपने क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं को जानने तथा उनको दूर करने के लिए कार्य भी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा के आयोजन से पहले महिलाओं की एक आमसमा का आयोजन किया जाता है। जिसमें ग्रामीण महिलाएं अपनी समस्याओं को सभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करती है। ग्रामसभा में उन समस्याओं पर विचार–विमर्श करके निवारण किया जाता, इस प्रकार ग्रामीण महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। सरकार के द्वारा प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। जिससे प्रत्येक महिला सुरक्षित हो सके। गाँव में महिला सशक्तिकरण केन्द्र खोले गये जो कि महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु जागरूक करते है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ स्वयं सहायता समुह से जुडकर अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत सरकार के द्वारा

ई–हाट शुरू किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ अपने स्वयं निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन कर सकती है। ग्रामीण महिलाएँ कमाने वाली, उद्यमी और बचतकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार, ग्रामीण महिलाओं में निवेश कई गुना लाभ लेकर आता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और विकसित करने में उनकी भूमिका उनमें निवेश को उनके पूरे समुदाय में निवेश बनाती है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नामक माइक्रोफाइनेंस मध्यस्थों के माध्यम से अपने परिवारों के लिए ऋण सुरक्षित करने और अन्य परिवारों को उधार देने के लिए बचत एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने से ग्रामीण समुदायों को होने वाले इन स्पष्ट लाभों के बावजूद, उन्हें जीवन के कई क्षेत्रों में लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और स्वच्छता तक पहुंच लैंगिक रूप से असंतुलित बनी हुई है। सामुदायिक भागीदारी अक्सर घर के पुरुष प्रमुखों की मंजूरी के अधीन रहती है, और लैंगिक भूमिकाओं पर प्रतिगामी विचार महिलाओं को उनकी आर्थिक क्षमता का एहसास करने से रोकते हैं। इसे महसूस करते हुए, विभिन्न सरकारें महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसे अभियान लेकर आई हैं। हालांकि ये सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, भारत को इस क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय बढ़ाने और वास्तविक समान अवसर के आगमन में तेजी लाने की जरूरत है।

ग्रामीण महिला नेतृत्व की चुनौतियाँ – किसी भी समाज के बदलाव और विकास की दशा, दिशा और गति हमेशा उसका नेतृत्व तय करता है। अपने लोकतांत्रिक भारतीय समाज में बात चाहे ग्रामीण स्तर में विकास की बात हो या फिर शहरी विकास की हर स्तर पर होने वाले चुनाव अपने देशकाल के अनुसार नेतृत्व का चुनाव करते हैं। नेतृत्व का प्रभाव कितना ज्यादा है यह हम अपनी रोजाना की जिंदगी में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 'सुबह की चाय के लिए आपकी जेब पर कितना प्रभाव पड़ेगा' या 'बुढ़ापे में मिलनेवाले पेंशन की राशि' ये सब देश का नेतृत्व तय करता है। लेकिन जैसे ही इस नेतृत्व के आगे महिला शब्द जुड़ता है तो समाज का नजरिया बदल जाता है।

जब भी गाँव में पंचायत चुनाव होते हैं तो प्रधानपति (वह पुरुष जिसकी पत्नी प्रधान हो) का होना कितना गलता है, हालांकि, इस बात पर चर्चा बहुत कम ही देखने को मिलती है कि आखिर क्यों जब कोई महिला प्रधान चुनी जाती है तो उसे उसकी अपनी पहचान की बजाय उसके पति की पहचान से ही जाना जाता है। जिले के एक गाँव की पूर्व महिला प्रधान या संरपच के साथ जब मेरे द्वारा इस विषय पर बात की तो उन्होंने एक वाकये के जरिए इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में जब उन्होंने खुद अकेले महिलाओं के बीच जाना शुरू किया और उनके साथ एक–दो बैठकें कीं तो गाँव में यह बात तूल पकड़ने लगी कि यह नयी नयी प्रधान या संरपच बनी है तो अपने आप को दिखा रही है, गाँव–गाँव घूमकर अपने मन से बैठक कर रही है, तो प्रधान बनने के बाद भी अपनी मनमानी करेगी। इन आलोचनाओं के बाद उन्होंने अपने पति के माध्यम से चुनाव प्रचार शुरू किया। इस बात पर चर्चा बहुत कम ही देखने को मिलती है कि आखिर क्यों जब कोई महिला प्रधान या सरपंच चुनी जाती है तो उसे उसकी अपनी पहचान की बजाय उसके पति की पहचान से ही जाना जाता है। साफ है कि जैसे ही कोई महिला अगर नेता बनने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाती है तो अपना समाज ही उसका पहला रोड़ा बनता है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर समाज महिला की योग्यता पर सवाल करे तो उसका जवाब देना संभव है, पर इसके विपरीत समाज चरित्र और अच्छी महिला की बनाई गई छवि के आधार पर महिलाओं पर सवाल खड़े करने लगता है। उन्हें यह बिलकुल भी रास नहीं आता कि कोई महिला खुद बिना किसी दूसरे (खासकर पुरुष) के नाम–पहचान की बजाय अपने नाम–पहचान, नजरिए और योजनाओं के साथ आमजन तक पहुंचे। इतना ही नहीं, जैसे ही कोई महिला प्रधान स्वतंत्र रूप से काम करने पंचायत भवन पहुंचती है, वहां उन्हें अपनी जगह बनाने में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में एक बार जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बात की तो उन्होंने बताया कि जब कोई महिला प्रधान पंचायत भवन में आती है तो यह बात बाकी के कर्मचारियों को नहीं भाती है। अगर महिला प्रधान खुद से कोई निर्णय ले या कोई काम करना चाहे तो सभी उसके रास्ते में रोड़ा बनने लगते हैं। गौर करनेवाली बात यह भी है कि जब हम लोग महिला प्रधान की बात करते हैं तो उसकी छवि हमेशा हमारे मन में एक बहु की ही होती है। मतलब एक शादीशुदा महिला की, क्योंकि शादीशुदा महिला को ही अपना समाज वैध मानता है। पितृसत्तात्मक समाज सुहाग के सारे ऋगांर से लैस महिला को अपने विशेषाधिकार में से शर्त के अनुसार थोड़ी जगह देने को तैयार होता है। अब जब समाज की नजर में 'वैध शादीशुदा महिला' को अपने नाम के पद को काम के पद में बदलने में इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में अविवाहित महिला के लिए इस पद तक पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

यह तो बात हुई जब महिलाएं नेतृत्व में होती हैं तो उन्हें किन बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ता। लेकिन जब हम महिला नेता को लेकर समाज के नजरिए पर गौर करें तो हमेशा महिला नेता के प्रति नकारात्मक छवि ही देखने को मिलती है। जैसे ही कोई महिला गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाए या किसी काम की तरफ अपने कदम बढ़ाती है तो उसे नेता की उपाधि दी जाने लगती है, जो एक तंज होता है। महिला नेता के नाम पर गंदी गालियां और भद्दे कमेंट तो बहुत आम हैं। उनके नेतृत्व को स्वीकार करना तो दूर उन्हें बोलने और काम करने की जगह देने तक हमारा समाज तैयार नहीं होता है।

महिला नेता की इन्हीं चुनौतियों के तोड़ के रूप में पितृसत्ता ने अपना सुरक्षा नियम अपनाया है, जिसमें महिला नेता के साथ प्रधानपति जैसे तमाम अप्रत्यक्ष पुरुष नेता को बढ़ावा दिया जाता है, जो महिला नेताओं को कठपुतली बनाकर खुद काम करते हैं। अब हो सकता है आप ये कहें कि महिला जब नेता बनने की तरफ कदम बढ़ाती है तो उसे डटे रहना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए और अपनी जगह खुद बनानी चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक बार आपको इस बात पर मंथन करने की जरूरत है कि संविधान ने समानता के अधिकार के तहत महिलाओं को वोट देने से लेकर नेता बनने का समान अधिकार तो दे दिया। महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए तो अब तक बहुत काम किए गए है, लेकिन अब जरूरत है महिला नेतृत्व को स्वीकार करने वाली जमीन तैयार करने की, जहां महिलाओं को अच्छी या बुरी महिला की बजाय इंसान के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि योग्यता और नेतृत्व क्षमता का महिला या पुरुष होने से कोई लेना–देना नहीं है।

शोध उद्देश्य – ''ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की समकालीन भूमिका व चुनौतियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) लिया गया है।

शोध परिकल्पना – ''ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की समकालीन भूमिका व चुनौतियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन''(सतना जिले के विशेष संदर्भ में) ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व कौशल में विकास हुआ है।

अध्ययन की आवश्यकता – भारतीय महिलाएँ, और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएँ, घर के अंदर और बाहर भी कई सामाजिक और आर्थिक भूमिकाएँ निभाती हैं, लेकिन समाज में उनके योगदान को उचित मान्यता नहीं मिलती है। उन्हें केवल बाल स्वास्थ्य, पोषण आदि से संबंधित कार्यक्रम में ही सम्मिलित किया जाता हैं। इसका कारण पुरूषों व योजनाकारों द्वारा महिलाओं के योगदान और क्षमता को कम माना जाता है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन में ''ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की समकालीन भूमिका व चुनौतियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) का अध्ययन किया गया। इस शोध अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं का चयन कर उनसे ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व से संबंधित कथनों का प्रतिउत्तर प्राप्त कर आंकड़ों का सारणीयन ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुतीकरण विश्लेषण व विवेचना की गई है। चयनित 50 ग्रामीण महिलाओं को लिया गया है।

शोध उपकरण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में ''ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की समकालीन भूमिका व चुनौतियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) से संबंधित कथनों का प्रतिउत्तर ज्ञात करने के लिए एक अनुसूची का निर्माण किया गया है। अनुसूची का प्रथम भाग उत्तरदात्री की पारिवारिक जानकारी से सम्बन्धित है जिसके अंतर्गत शिक्षा, श्रेणी, आयु, वैवाहिक स्थिति तथा व्यावसायिक जानकारी आदि सम्मिलित है। अनुसूची का द्वितीय भाग ''ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की समकालीन भूमिका व चुनौतियों से सम्बन्धित कथन है। जिसमें 05 कथन है। जिनके उत्तर हाँ या नहीं में पूछे गए हैं।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध की प्रकृति सारणीयन, विवरणात्मक व विश्लेषणात्मक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बदलती तस्वीर व उनके विकास में सहयोगिता के बारे में जानने के लिए शोध संरचना के विवरणात्मक प्रकार को अपनाया गया, तथ्यात्मक व वास्तविकता को जानने के लिए सहभागी शोध प्रविधि को आधार बनाया गया है।
प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध उपकरण के रूप में स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची है। उक्त उपकरण का उपयोग कर संकलित आंकड़ों का सारणीयन व ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया है। शोध अध्ययन हेतु 50 ग्रामीण महिलाओं का चयन किया गया है।

आंकड़ों का संकलन – प्रस्तुत शोध अध्ययन में आंकड़ों के संकलन हेतु सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं को शोघ उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए अत्यन्त संवेदनापूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रदत्तों का संकलन किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों का संकलन सन्दर्भ पुस्तकों, प्रतिवेदन, शोध साहित्य, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार–पत्र, प्रकाशित व अप्रकाशित शोध साहित्य एवं इंटरनेट से लिया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन को वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक बनाने के उद्धेश्य से तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोतो से सूचनाओं व तथ्यों का सकंलन किया।

प्राथमिक स्त्रोत के रूप में – प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक स्त्रोत अनुसूची के माध्यम से शोध से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने के लिए शोधार्थी द्वारा ग्रामीण महिलाओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया गया।

द्वितीयक स्त्रोत के रूप मे ं– प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों से सूचनाएँ एकत्रित की गई इसी क्रम में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, समाचार पत्रों, विषय से संबंधित पुस्तकों पत्र, पत्रिकाओं, संबंधित शोध पत्र, संबंधित शोध ग्रन्थ तथा इन्टरनेट में उपलब्ध जानकारी से अध्ययन सामग्री का अध्ययन किया गया।

सांख्यिकी विश्लेषण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में सांख्यिकीय पद्धतियों के माध्यम से संकलित आंकड़ों का व्याख्यात्मक वर्णन किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में इस पद्धति के माध्यम से आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया है। सांख्यिकीय पद्धति में उत्तरादात्रीयों से साक्षात्कार कर अनुसूची में प्रथम भाग में सामान्य जानकारी तथा द्वितीय भाग में ''ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की समकालीन भूमिका व चुनौतियो'' से संबंधित कथनों की जानकारी पूछी गयीहै।

चित्र 1: आपकों लगता है कि ग्रामीण विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

तालिका क्रमांक 01: ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व से संबंधित कथन

क्रं.	कथन	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	कुल योग	प्रतिशत
1	आपकों लगता है कि ग्रामीण विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।	42	84	08	16	50	100
2	आपको ये लगता है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यदि महिलाओं को जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो वे घर और गांव के विकास के कार्यों को वे बाखूबी निभा सकेगीं।	37	74	13	26	50	100
3	आपको लगता है कि पुरूष प्रधान समाज ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास में कई बार बाधा बन जाते हैं।	39	78	11	22	50	100
4	आपको सरकार द्वारा महिला विकास हेतु चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी हैं।	41	82	9	18	50	100
5	शिक्षा के प्रसार प्रचार से व सरकारी योजनाओं के माध्यम से आपके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।	50	100	–	–	50	100

स्त्रोत – अनुसूची से प्राप्त

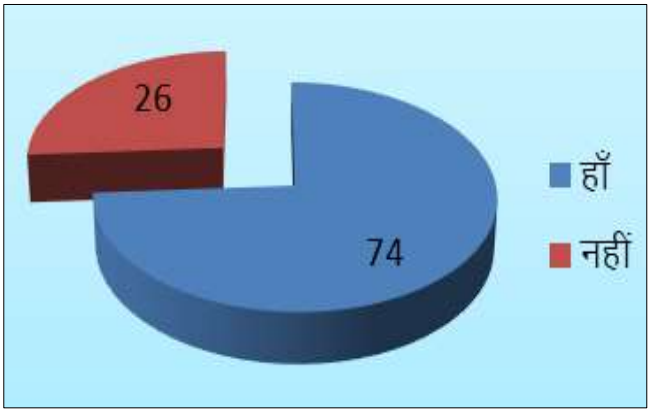

चित्र 2: आपको ये लगता है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यदि महिलाओं को जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो वे घर और गांव के विकास के कार्यों को वे बाखूबी निभा सकेगीं।

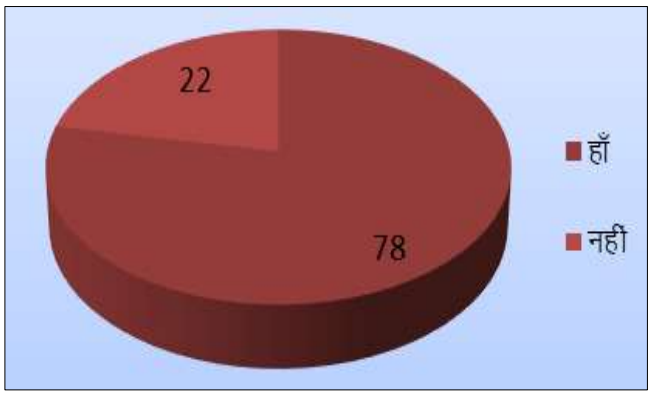

चित्र: 3 आपको लगता है कि पुरूष प्रधान समाज ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास में कई बार बाधा बन जाते हैं।

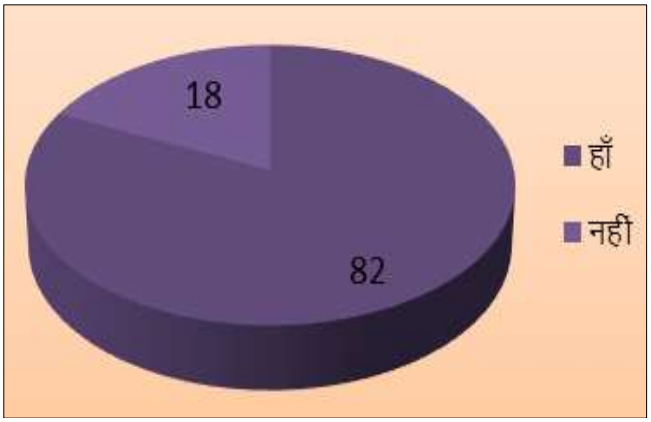

चित्र 4: आपको सरकार द्वारा महिला विकास हेतु चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी हैं।

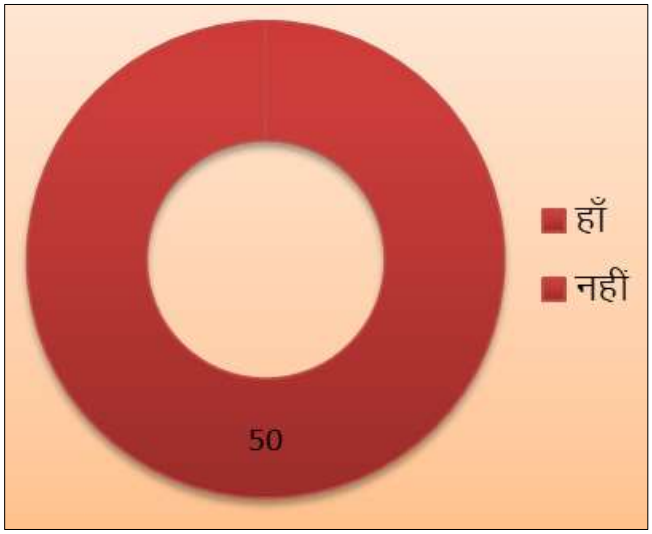

चित्र 5: शिक्षा के प्रसार प्रचार से व सरकारी योजनाओं के माध्यम से आपके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

आंकड़ों का विश्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में अनुसूची में पूछे गए कथन क्रमांक

1. ग्रामीण विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, में 84 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओ ने हाँ में तथा 16 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओ ने नहीं में प्रतिउत्तर दिया। वहीं कथन क्रमांक –
2. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यदि महिलाओं को जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो वे घर और गांव के विकास के कार्यों को वे बाखूबी निभा सकेगीं, में 74 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओ ने हाँ में तथा 26 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओ ने नहीं में प्रतिउत्तर दिया। जबकि कथन क्रमांक –
3. पुरूष प्रधान समाज ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास में कई बार बाधा बन जाते हैं, में 78 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओ ने हाँ में तथा 22 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओ ने नहीं में प्रतिउत्तर दिया। इसी तरह कथन क्रमांक –
4. सरकार द्वारा महिला विकास हेतु चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी हैं, में 82 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओ ने हाँ में तथा 18 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओ ने नहीं में प्रतिउत्तर दिया। इसी तरह कथन क्रमांक –
5. शिक्षा के प्रसार प्रचार से व सरकारी योजनाओं के माध्यम से आपके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, में 100 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओ ने हाँ में प्रतिउत्तर दिया है। जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उपरोक्त शोध पत्र की परिकल्पना सार्थक पायी गयी है।

शोध परिणाम – प्रस्तुत शोध अध्ययन ''ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की समकालीन भूमिका व चुनौतियों का

समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) में प्राप्त परिणामों के आधार पर किया गया है।

प्रस्तुत शोध के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि परिकल्पना ''ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की समकालीन भूमिका व चुनौतियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व कौशल में विकास हुआ है।

विवेचना – भारत की 833.8 मिलियन–मजबूत ग्रामीण आबादी में से लगभग आधी संख्या महिलाओं की है जो नए भारत की विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. पिछले कुछ दशकों में, भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लैंगिक मुख्यधारा और महिला सशक्तिकरण में आश्चर्यजनक नवाचार देखे गए हैं. इनमें 1990 के दशक से लागू किए जा रहे लिंग संवेदीकरण प्रयासों से लेकर, एक मिलियन से अधिक महिलाओं को जमीनी स्तर पर शासन का नेतृत्व करने के लिए चुनकर सक्षम बनाने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधन जैसी पहल शमिल हैं. वर्तमान समय में, तेजी से बढ़ रहे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और उद्यमों का ग्रामीण नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान है। स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क के विकास के साथ ही इसके जनादेश का भी विस्तार हुआ है ताकि एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में सेवाएं प्रदान की जा सकें, गरीबों के लिए निवेश जुटाया जा सके और प्रशिक्षण तथा कौशल के साथ संलग्नता को मजबूत किया जा सके (दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से). इन अवसरों के साथ, दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम की उप–योजना– स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ने ग्रामीण स्टार्ट–अप के तीन प्रमुख स्तंभों – वित्त, इनक्यूबेशन और कौशल तंत्र की व्यवस्था करते हुए महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाया है.

आजीविका के विविधीकरण को सुनिश्चित करने और रोजगार सृजन के अप्रयुक्त अवसरों को बढ़ावा देने के लिए गैर–कृषि क्षेत्र के साथ कौशल और क्षमता निर्माण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर, जमीनी स्तर की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य संघबद्ध संस्थानों से लेकर राज्य–स्तरीय प्रशिक्षण संगठनों तक सह संलग्नता और जिला क्षमता निर्माण प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है।

स्वयं सहायता समूहों और महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण स्टार्ट–अप की भूमिका को केंद्रीय बजट 2021 से एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रोत्साहन मिला है, जिसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने महिलाओं को भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रमुख भागीदार के रूप में वर्णित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट–अप्स के बढ़ने से विभिन्न क्षेत्रों – खाद्य प्रसंस्करण, देखभाल उद्योग, रीसाइक्लिंग, जैविक खेती और स्थानीय शिल्प में उनकी पहचान बन रही है. इन महिला ग्रामीण उद्यमों ने महिलाओं की समानता और उनके सशक्तिकरण (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए समावेशी और परस्पर नीतिगत प्रयासों के साथ) के लिए अवसर प्रदान किये।

निष्कर्ष

भारत वर्ष एक सम्पन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध देश है, जहां महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान रहा है। ग्रामीण परिदृश्य में महिलाओं की बड़ी आबादी है। वर्तमान समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय की ओर प्रोत्साहित कर इन्हे आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है। विशेषकर कृषि प्रसंस्करण उद्योगों, बैंकिंग सेवाओं और डिजिटलीकरण की सहायता से महिलाओं के सामाजिक और वित्तीय सशक्तिकरण की शुरुआत की जा रही है। महिलाओं में जन्मजात नेतृत्व गुण समाज के लिए संपत्ति हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिघम यंग ने ठीक ही कहा है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इसलिए, यह इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम ''एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता'' है। भारतीय इतिहास महिलाओं की उपलब्धि से भरा पड़ा है।

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राप्त परिणामों के आधार पर आंकड़ों के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं का योगदान निरन्तर बढ़ता ही रहा है। महिलाएँ आत्मनिर्भर बनकर ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर रही है। सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओ के विकास के लिए कई योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकत्तर महिलाएँ कृषि आधारित कार्यों को प्राथमिकता देती थी, लेकिन वर्तमान समय में महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करके गांवों का विकास कर रही है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिलाएं न केवल खुद को सशक्त बना रही हैं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की मजबुती में को भी योगदान दे रही है। सरकार के निरन्तर लगातार आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी भागीदारी दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 6–7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों का अभियान और तेज हुआ है। आज देश भर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं। महिलाओं के पराक्रम को समझने की जरूरत है, जो हमें महिमा की अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आइए हम उन्हें आगे बढ़ने और फलने–फूलने में मदद करें। महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए 'अमृत काल' इन्हें समर्पित हो।

ग्रामीण महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए स्टैंड–अप इंडिया, और स्टार्ट–अप सम्बन्धि कई योजनाएं शुरू की हैं। अब एक महिला उद्यमिता मंच पोर्टल का गठन करना एक प्रमुख पहल है, जो नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। यह अपनी तरह का पहला एकीकृत पोर्टल है जो विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक पटल देता है और उन्हें कई प्रकार के संसाधनों, की सुविधा प्रदान करता है। ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्रों मे पावं रखने के लिए महिला स्टार्ट–अप महत्वपूर्ण है। अब महिलाओं ने पूरी उर्जा के साथ उद्यमिता के क्षेत्रों में पांव जमाए हैं। बैन एंड कंपनी और गूगल के अनुसार, महिला उद्यमी 2030 तक लगभग 150–170 मिलियन नौकरियां पैदा करेंगी। एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार, 2018–21 तक स्टार्टअप्स द्वारा लगभग 5.9 लाख नौकरियां पैदा की गईं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के माध्यम से शुरू से ही उद्यमिता के बीज बोने का सार्थक प्रयास किया जा चुका है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सूक्ष्म आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित व निर्धनता समाप्ति हेतु कार्यक्रम को संचालित करना शामिल है ताकि सेवाओं के अन्तर्गत महिलाओं का गत्यात्मक स्वरूप विद्यमान रह सके। सूक्ष्म ऋण, उपभोग व उत्पादन हेतु वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, कार्य की सहभागिता में वृद्धि करने का एक प्रयास है जो आर्थिक सहयोग की पुरानी रणनीति व कार्ययोजना को पुनर्संशोधित करता है। वैश्वीकरण के लगातार बढ़ते असमान प्रभावों ने लिंग भेदभाव को अर्थतंत्र मे संचालित किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनके लिये असुरक्षित वातावरण का सृजन हुआ है। कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण महिलायें सशक्त रहे इसके लिए मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, दुग्ध उद्योग का विकास, छोटे पशुओं की देखभाल, मुर्गीपालन, मछलीपालन को

बढ़ावा देना एक रणनीतिक कदम है। इनके कार्य प्रतिशत को इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) व कृषि उद्योग में बढ़ाना है तथा रात्रिकालीन कार्यों हेतु सुरक्षा, पारदर्शिता तथा परिवहन की सुविधा प्रदान करना है। इन सेवाओं को महिलाओं हेतु मित्रवत् बनाकर उनकी कार्यक्षमता तथा लिंग समानता में वृद्धि किया जा सकता है।

सुझाव

- महिलाओं के विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्माण।
- पुरुषों के साथ महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में वैधानिक एवं समान अवसर प्रदान करना।
- देश के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी।
- स्वास्थ्य, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, रोजगार में समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा आदि तक समान पहुँच।
- महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन का प्रयास।
- सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहार और कुप्रथाओं में परिवर्तन।
- विकास प्रक्रिया में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन।
- नागरिक समाज विशेषकर महिला संगठनों के साथ भागीदारी का निर्माण एवं उन्हें सुदृढ़ करना।

सन्दर्भ सूची

1. शर्मा, बी.एम. (1999) भारत में महिला सशक्तिकरण मूल प्रश्न, उदयपुर पृ.70
2. मौर्य, शैलेन्द्र (2007) राजस्थान में महिला विकास प्रारम्भ से आज तक, राजस्थान साहित्य संस्थान, जोधपुर पृ. 117
3. कपूर ए.के. सिंह, धर्मवीर (1997) रूरल डेवलपमेन्ट एन.जी. ओ. रावत पक्निकेशन, नई दिल्ली पृ.99
4. देवी, मंजू के. (1997) सरल वूमेनः पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, अनमोल पब्लिकेशन प्रा.लि. नई दिल्ली पृ.24
5. शर्मा, संगीता (2005) महिला विकास एवं राजकीय योजनाएँ, रितु पक्निकेशन, जयपुर।
6. जैन. मंत्र (1994) कार्यशील महिलाएं एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रिन्टवल, जयपुर,।
7. विद्या, क.मी. (1997) पालिटिकल एम्पायरमेन्ट ऑफ वुमन एट द ग्रास स्ट कनिष्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
8. www.google.com.
9. https://www.thinkwithniche.in/blogs/details/women-empowerment-and-economic-growth
10. https://www.epw.in/tags/women
11. https://www.samareducation.com/2022/04/role-of-women-in-economic-development-in-hindi.html